

रोहंगिया मुद्दे पर बांग्लादेश-म्यांमार समझौता

चर्चा में क्यों?

बांग्लादेश ने रोहंगिया मुसलमानों की वापसी के लिये म्यांमार के साथ समझौता किया है। इसके तहत बांग्लादेश में शरणार्थी बनकर रह रहे लगभग 6.2 लाख रोहंगिया मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (UNHCR), म्यांमार और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए बना एक संयुक्त कार्यशील समूह इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ करेगा। शरणार्थियों को वापस भेजने का यह समझौता अक्टूबर 2016 के बाद म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आए मुसलमानों पर लागू होगा। यह समझौता उन 2 लाख मुसलमानों पर लागू नहीं होगा, जो अक्टूबर 2016 के पहले बांग्लादेश आए हैं।

रोहंगिया मुसलमानों के पलायन का कारण

म्यांमार के रखाइन राज्य में अगस्त में सेना द्वारा रोहंगिया चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने बाद रोहंगिया मुसलमानों का पलायन शुरू हो गया था। इसके बाद छह लाख से ज्यादा रोहंगिया मुसलमानों को बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी।

चीन की दलित्वादी

इस समझौते का स्वागत हालाँकि कई देशों ने किया है, लेकिन इस समझौते में चीन द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं गई है। चीन ने रोहंगिया समस्या के लिये त्रिसंघीय समाधान का समर्थन किया है-

- रखाइन में युद्ध वरिष्ठ।
- रोहंगिया शरणार्थियों के म्यांमार-प्रत्यावर्तन के लिये द्विपक्षीय समझौता।
- रोहंगिया इलाकों के विकास के अतिरिक्त दीर्घकालिक उपायों की खोज।

चीन द्वारा इस मुद्दे में रुचि दिखाने का कारण यह है कि रखाइन क्षेत्र के अंतर्गत चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 10 अरब डॉलर का आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा भी शामिल है। साथ ही चीन ने संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार पर लगाए जाने वाले संभावित अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से संरक्षण प्रदान किया है।

अन्य तथ्य

- शरणार्थियों की सहायता के लिये काम करने वाली एजेंसियों ने रोहंगिया शरणार्थियों को ज़बरदस्ती म्यांमार भेजने पर उनकी सुरक्षा पर चिंता जताई है।
- अमेरिका ने रोहंगिया-नरसंहार को 'जातीय समूह को साफ' करने की कार्रवाई बताया था।
- रूस के अनुसार यह समझौता रोहंगिया समस्या का वास्तविक समाधान नहीं है। इससे स्थिति और बगिड़ सकती है।
- बांग्लादेश ने कहा है कि दोनों पक्षों ने दो महीने में शरणार्थियों की म्यांमार में वापसी शुरू कराने पर सहमति जताई है।